(ड़) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ड़) मौजूदा नीति के अनुसार लोहे और इस्पात का निर्यात निर्बाध रुप से किया जा सकता है। लोहे और इस्पात का निर्यात और वह स्थान, जहां निर्यात किया जाना है, अनेक घटकों जैसे घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय मांग, घरेलू मूल्य, आयातकर्ता देशों में इस्पात के मूल्य इत्यादि पर निर्भर करता है। ये घटक समायतः परिवर्तनशील हैं और बार-बार बदलते रहते है। मौजूदा बाजार परिस्थितियों के आधार पर उद्यमी स्वंय ही निर्यात-बाजार तलाश करते हैं और निर्यात करते है।

इस्पात मंत्राल्य ने लोहे और इस्पात के निर्यात के संबंध में एक विशेषज्ञ दल गठित किया था जिसने हाल ही में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया है कि भारतीय इस्पात उत्पादकों को तेजी से बढ़ रहे दक्षिण-पूर्व एशियाई, पूर्वी एशियाई और चीन के बाजारों पर ध्यान देना चाहिए। इस रिपोर्ट में जापान, अमरीका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप में अवसरों के बारे में भी उल्लेख किया गया है और यह सुझाव दिया गया है कि पाकिस्तान को निर्यात करने के अतिरिक्त बांग्लादेश, श्रीलंका,म्यांमार आदि जैसे अन्य पड़ौसी देशों में बाजार दृढ़ करने के प्रयास करने चाहिए।

निर्यात करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय करना शामिल हैं:-

(1) विनियम की बाजार दर पर निर्यात से हुई आय की पूर्ण परिवर्तनीयता,

(2) अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत निर्यातकों को अपनी आवश्यकता का कच्चा माल शुल्क मुक्त मंगाने की सुविधा उपलब्ध कराना,

(3) निर्यात किए जाने वाले सामान के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले किसी आयातित अथवा उत्पाद शुल्क वाले माल पर दिए गए शुल्क की वापसी, और

(4) धारा 80 एच.एच.सी. के तहत् निर्यात से हुई आय पर आयकर से छूट।

SAIL Unit in Assam

999. DR. MOHAN BABU: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether SAIL has planned to set up a unit in Assam;

(b) if so, the details thereof including the investment to be made and production capacity; and

(c) by when the project is likely to start?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) and (b) A Galvanising unit with a production capacity of 40,000 tonnes per annum of corrugated/plain sheets with an investment of around Rs. 42.85 crores has been planned to be set up by Steel Authority of India Limited (SAIL) in Assam.

(c) The work on the Project is in hand of SAIL.

Equity participation by SAIL in Australian Company

1000. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Steel Authority of India propose to acquire 14.8% stake in an Australian Company that mines coking coal;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if so, the reasons that weighed with the Steel Authority of India for diversifying its activities in out sourcing the inputs instead of sticking to its core competence?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) It will not be in, commercial interest of SAIL to disclose any details of the proposal as it is at a very preliminary stage and SAIL is subjected to secrecy obligations in this regard.

(b) and (c) Do not arise in view of (a) above.

Use of new Steel Technology to reduce Coal consumption

1001. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to obtain new steel technology by SAIL from Japan to reduce coal consumption;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that SAIL plants are using absolut equipment and technical skills;

(d) whether it is a fact that the steel plant at Visakhapatnam is reporting higher operational costs; and

(e) if so, the steps preposed to rectify such problems?

THE MINISTER OP STEEL AND MINISTER OP MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) No. Sir.

(b) Does not ((rise in view of (a) above.

(c) No, Sir.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise in view of (d) above.

Implementation of Dharti Putra Welfare Scheme

1002. SHRI GOVINDRAM MOU:
SHRI PARAG CHALIHA:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the details of States selected for "Dharti-
Putra Welfare Scheme" and names of States where this scheme has already been implemented;

(b) whether a number of proposals alongwith- the amount involved therein were submitted by some Govemment under this Scheme;

(c) if so, die details thereof; and

(d) the time to be taken for finally deciding the clearance of diese proposals?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) There is no such scheme being implemented by die Ministry.

(b) to (d) Does not arise.

आंठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए खर्च की गई/प्रस्तावित धनराशि

1003. **श्री रामजीलाल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजन के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना में इन जातियों/पिछड़े: वर्गों के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि प्रस्तावित है?

कल्याणं मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए व्यय इस प्रकार है:-

1. अनुसूचित जाति विकास रुपए 2756.59 करोड़

2. अनूसूचित जनजाति विकास रुपए 1974.61 करोड़

3. पिछड़ा वर्ग विकास रुपए 117.08 करोड़

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए निम्नलिखित धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।

1. अनुसूचित जाति विकास रुपेए 13774.69

2. अनुसूचित जनजाति विकास रुपए 7406.47 करोड़

3. पिछड़ा वर्ग विकास रुपए 5972.50 करोड़

Committee to study the functioning of NGO's

1004. SHRI VED PRAKASH P. GOYAL: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Govemment have appointed a Committee to study the functioning of Non-Govemment Organisations in die country to ensure that funds provided by Government are properly utilised;

(b) me amount of funds received by Non-Government Organisations from foreign countries and purpose thereof during last five years;

(c) whether Govemment have come across any irrequlanities in the working of Non-Govemment Organisations; and

(d) the details of die terms of reference of above Committee?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) and (d) The proposal is under active consideration of the Govemment.

(b) This is regulated by the Ministry of Home Affairs and no separate record is maintained in respect of NGO's working in Welfare sector.